■ संक्षिप्त समाचार

www.sanjanabharati.com | दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित | facebook.com/Sanjanabharati

SB NEWS

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHI/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 नारी देह, नारी अधिकार: माहवारी पर सुप्रीम... | 3 2026-27 के बजट से शक्तिपुंज बनेगा भारत: सुभाष | 4 टैलेंट से सफल अभिनेत्री और गायिका बनीं हैं...

वर्ष: 10 | अंक: 101 | दिल्ली, मंगलवार, 3 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

अशोकनगर कॉल सेंटर को सिंधिया ने घोषित किया जिले का नया 'नवरत्न'

अशोकनगर (एजेन्सी)। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अशोकनगर के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। केन्द्रीय मंत्री ने अशोकनगर के लिए रोजगार, सिंचाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित कई क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। इस बैठक में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अशोकनगर की गहन दिशा बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के समग्र विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसेवा की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, अधोसंरचना, रोजगार, उद्योग और नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा हुई तथा विभिन्न विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

हरियाणा मंत्रिमण्डल ने स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बदलाव को दी मंजूरी

चंडीगढ़ (एजेन्सी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 तथा हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक फीस और शुल्कों में संशोधन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले से दोनों नियमों के संबंधित शेड्यूल में संशोधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है ताकि मौजूदा फीस संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और शहरी विकास की जरूरतों के अनुरूप तर्कसंगत और अद्यतन किया जा सके। मंजूर किए गए प्रस्ताव में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के तहत स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, राज्य अवसंरचना विकास शुल्क, अवसंरचना संवर्धन शुल्क और आईएसी-टीओडी में संशोधन शामिल है। इसके अतिरिक्त, साथ ही हरियाणा हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत जांच शुल्क और परिवर्तन शुल्क में भी बदलाव किया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में सबसे निर्धन और आकांक्षी मध्यम वर्ग के लिए प्रावधान

'कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किसान सशक्त और सुरक्षित बनेंगे'

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी-संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देता है और अगले पच्चीस वर्षों के लिए दूरदर्शी कार्ययोजना प्रदान करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित बजट उपरांत मीडिया संवाद में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट को पूरी तरह समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह संरचनात्मक सुधार पर स्पष्ट, क्रमबद्ध दृष्टिकोण दशार्ता है। संरचनात्मक सुधार अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा संचालित हैं, और अत्याधुनिक तकनीकें तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से युक्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों से संरचनात्मक सुधार के रुख ने इस बजट को स्वाभाविक रूप से भविष्योन्मुखी बना दिया है और अब इसके दीर्घकालिक लाभों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया सहित जानकार हितधारकों की है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने मध्यम वर्ग को मिलने वाले लाभों से संबंधित चिंताएं दूर करते हुए कहा कि बजट का वास्तविक प्रभाव अल्पकालिक आय गणना की बजाय बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल और जीवन यापन खर्च से दीर्घकालिक राहत में निहित है। उन्होंने कहा कि जैव-फार्मा, निदान, टीके और जीन-आधारित उपचारों में व्यापक निवेश से कैंसर, मधुमेह और चयापचय (भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना) संबंधी विकारों जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम होगा। भारत की बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में 11-12 करोड़ से अधिक मधुमेह रोगी, लगभग 14 करोड़ इसके पूर्व अवस्था के रोगी और कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2030 तक प्रति वर्ष 20 लाख ऐसे मामले सामने आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि घरेलू जैव-उत्पादित किफायती दवाएं, टीके और निदान उपकरण, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और कमजोर वर्गों के लिए बड़ा सामाजिक और आर्थिक सहारा साबित होंगे।

डॉ. सिंह ने 10 हजार करोड़ रुपये की बायोफार्मा शक्ति पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत पहले ही वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरकर वैश्विक स्तर पर तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष जैव-अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह नया निवेश बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, टीकों, चिकित्सा उपकरणों और जीन-आधारित प्रौद्योगिकियों में क्षमता विस्तारित कर भारत की स्थिति और सुदृढ़ बनाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी को अगला प्रमुख औद्योगिक चालक बताया, जो पिछले दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई भूमिका के तुलनीय है। उन्होंने कहा कि आगामी औद्योगिक क्रांति जैव-क्रांति होगी, जिसमें पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और उन्नत जीवन-विज्ञान नवाचार शामिल होंगे।

पहली बार 10,000 एकड़ भूमि को रिज फॉरेस्ट घोषित किया गया-सिरसा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। विश्व वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वेटलैंड्स को जीवन, संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षा की आधारशिला बताते हुए कहा कि जल स्त्रोतों का संरक्षण पर्यावरण के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी होने के साथ साथ हमारी परंपराओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया है और दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व भी उसी दिशा में ठोस और परिणामकारी कदम उठा रही है।

श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली में कभी 1000 से अधिक जल स्त्रोत मौजूद थे, जो समय के साथ अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सभी जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार का संकल्प लिया है और लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2027 के अंत तक अधिकतम जल निकायों को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की असोला भाटी स्थित ऐतिहासिक नीली झील को रामसर साइट घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कार्य किया जा रहा है।

पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली रिज को दिल्ली की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि पिछले कई दशकों की उपेक्षा के बाद पहली बार 10,000 एकड़ भूमि को रिज फॉरेस्ट घोषित किया गया है। इसके लिए एक वर्किंग प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अगले चार वर्षों में रिज क्षेत्र में लगभग 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ताकि दिल्ली के हरित क्षेत्र को नई ऊर्जा दी जा सके।

प्रदूषण नियंत्रण पर बोलते हुए श्री सिरसा ने कहा कि वेटलैंड्स प्राकृतिक रूप से वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार तकनीकी नवाचारों को भी बढ़ावा दे रही है, जिनके माध्यम से जल स्त्रोतों के आसपास PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कणों को कैप्चर कर प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकेगा।

सिंगापुर की कम्पनी एपी मोलर माएर्स्क के प्रमुख ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को विदेशी निवेशकों से निरंतर समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में सिंगापुर की अग्रणी एकीकृत कंटेनर लॉजिस्टिक्स कंपनी एपी मोलर माएर्स्क के प्रबंध निदेशक रीन पील पेडरसन ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। पेडरसन के साथ विवेक शर्मा, हेड बिजनेस डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अफेयर्स (भारत, बांग्लादेश एवं श्रीलंका क्षेत्र) भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं, उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल तथा राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में शामिल है और यहां निवेशकों के लिए सुरक्षित, स्थिर और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम, त्वरित स्वीकृतियां, नीति आधारित प्रोत्साहन और मजबूत कानून व्यवस्था के माध्यम से सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। उन्होंने एपी मोलर माएर्स्क को राज्य में अपने निवेश का विस्तार करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार आवश्यक भूमि, कनेक्टिविटी और नीतिगत सहयोग सुनिश्चित करेगी।

इस अवसर पर विवेक शर्मा ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों और यहां के निवेश अनुकूल माहौल को लेकर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा की। हमारी कंपनी पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से इस राज्य में निवेश कर रही है। इस विशेष चर्चा के दौरान हमने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण और अपने व्यवसाय के विस्तार में राज्य सरकार से मिले पूर्ण सहयोग को लेकर अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए। हम भविष्य में भी उत्तर प्रदेश में अपने कारोबार के विस्तार के लिए नए निवेश अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।

उल्लेखनीय है कि एपी मोलर माएर्स्क शिपिंग, बंदरगाह, जल परिवहन और अंतर्देशीय लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की कंपनी है। इसके संभावित निवेश से उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूती, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा विभिन्न यूनियनों के साथ बैठक, जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के राजस्व एवं आवास निर्माण व शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज विभिन्न यूनियनों के साथ मैराथन बैठकें कीं। पंजाब भवन में आयोजित इन बैठकों में रेवेन्यू पटवार यूनियन, कानूनगो यूनियन, साझा मुलाजम मंच पुड्डा और ऑल इंडिया अतिवाद पीड़ित एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से विभिन्न मीटिंगों के दौरान कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी हर जायज मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्व मंत्री ने विभिन्न एसोसिएशनों और यूनियनों द्वारा रखी गई मांगों को ध्यान से सुना।

उन्होंने बताया कि जो मांगें विभागीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाएगा। वहीं जो मांगें मुख्यमंत्री या वित्त विभाग के स्तर पर हल होनी हैं, उन्हे पूरा करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ बैठक की जाएगी।

राजस्व मंत्री ने पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले पटवारियों और कानूनगोओं को सरकार द्वारा सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से करें। इसके अलावा साझा मुलाजम मंच, पुड्डा मोहाली के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का लाभ देने के मामले को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।

ऑल इंडिया अतिवाद पीड़ित एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों के बारे में कैबिनेट मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिया कि एसोसिएशन द्वारा रखी गई जायज मांगों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनके समाधान के लिए हर संभव और उचित कदम उठाए जाएंगे।

मीटिंग के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) श्री अनुराग वर्मा तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शाह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते का किया स्वागत

(एजेंसी)।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 18 प्रतिशत की कम शुल्क (टैरिफ) दर के साथ हुआ यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इससे व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे तथा परस्पर विकास को बढ़ावा मिलेगा। शाह ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों और उनके नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा तथा इससे भारत एवं अमेरिका के बीच व्यापार के और फलने-फूलने की उम्मीद है।

नगर निगम चुनाव को लेकर गौ रक्षा परिषद की बड़ी बैठक

गौवंश हितैषी उम्मीदवार को ही मिलेगा समर्थन: स्वामी विश्वमित्रानंद गिरी

संजना भारती संवाददाता

पंचकूला। बरवाला स्थित नग्गल गौशाला में गौ रक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विश्वमित्रानंद गिरी जी ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी नगर निगम चुनावों में संगठन की भूमिका और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।

कूड़े के ढेर से गौ माता को मुक्त कराने का संकल्प बैठक को संबोधित करते हुए स्वामी विश्वमित्रानंद गिरी ने स्पष्ट किया कि इस बार नगर निगम चुनाव में गौ रक्षा परिषद केवल उसी प्रत्याशी का समर्थन करेगी, जो गौ माता को सड़कों और कूड़े के ढेर से हटाकर उन्हें सुरक्षित आश्रय देने का लिखित या सार्वजनिक वचन देगा। उन्होंने कहा, "यह अत्यंत दुखद है कि गौ माता को सड़कों पर कूड़ा खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर गौवंश के सम्मान की बात करें।"

जनता के बीच जाएगा संगठन स्वामी जी ने बताया कि परिषद के कार्यकर्ता इस बार सीधे जनता के बीच उतरेंगे। संगठन लोगों से अपील करेगा कि वे अपना बहुमूल्य वोट केवल उसी उम्मीदवार को दें जो गौवंश के हित में कार्य करने का जज्बा रखता हो। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे प्रतिनिधियों को जिताना है जो शहर की व्यवस्था सुधारने के साथ-साथ गौ सेवा को अपनी प्राथमिकता में रखें।

बैठक में उपस्थित गणमान्य इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से: मोहित शर्मा (प्रांत संगठन मंत्री), शेखर (प्रांत महामंत्री), मोहित कालरा (प्रांत महासचिव), गौतम शर्मा (जिला आईटी सेल प्रमुख), कृष्ण (गो ग्रास प्रमुख) एवं अन्य गणमान्य सदस्य शामिल थे। सभी पदाधिकारियों ने एकमत से स्वामी जी के निर्णय का स्वागत किया और चुनाव में गौ रक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया।

गुजरात की झांकी ने नई दिल्ली में रचा इतिहास

नई दिल्ली (एजेन्सी)। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात की झांकी ने लगातार चौथे वर्ष "लोकप्रिय पसंद श्रेणी" में प्रथम पुरस्कार जीता। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, सूचना आयुक्त के सचिव विक्रांत पांडे और किशोर बचानी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को विजेता ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव एमके दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार और सूचना आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर सुधार की गति को गति प्रदान करता है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट तीन मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है।

संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक फैसला-सीएम सैनी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के नाम से किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट का नाम दिया। यह नामकरण श्री गुरु रविदास महाराज जी के अमर आदर्शों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित करते हैं और हमें एक समरस, न्यायपूर्ण तथा मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। यह पहल उनके महान विचारों को सम्मान देने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल यह भी दशार्ती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण करता है जिन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य किया।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर देश के बड़े संस्थानों का नाम संत-महापुरुषों के नाम से कर रहे हैं, जो संत-महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले दिनों अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया था। इसी तरह से हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार का आम बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस बजट में हरियाणा को विशेष स्थान दिया गया है। बजट में सेम की समस्या से ग्रसित जमीन की बात की गई, एमएसएमई, इंडस्ट्री और एआई को विशेष स्थान दिया गया, जिसका लाभ सीधे हरियाणा को मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 55 साल सत्ता में रही लेकिन ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई। यह बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला है। यह युवाओं को रोजगार देने वाला है। यह किसानों को मजबूत करने वाला बजट है। किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां के लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब को यदि आगे बढ़ाना है तो भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को सिर्फ सब्ज-बाग दिखाए। पंजाब में पिछले दिनों बाढ़ आई, किसानों की फसल खराब हुई। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को 20 हजार रुपये एकड़ मुआवजा दिया और उनकी पार्टी के मुखिया गुजरात जाकर कह रहे हैं कि हमने किसानों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया। वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों का नुकसान हो गया और वह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किसानों की समस्या को समझा और 16 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया।

सम्पादकीय

वास्तविक चिंताओं से कटा बजट

मोदी सरकार ने एक बार एक ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है, जबकि धनपतियों के लिए पूरा मौका है कि वे अपनी तिजोरी का धन दोगुना-चौगुना कर लें। अमेरिका की तरफ से पड़ी टैरिफ की मार और बदलते भू राजनैतिक समीकरणों के बीच मोदी सरकार के पास बजट के रूप में एक अच्छा मौका था, जब वह आम आदमी की चिंता को सीधे संबोधित करती और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं का हल पेश करती। लेकिन जैसे नरेन्द्र मोदी आज की बात न कर या तो हजार साल पहले की बात करते हैं या आने वाले सौ साल में देश कहां हो सकता है, इसके सपने दिखाते हैं। तो बजट में भी ऐसे ही दूर के सपने दिखाए गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम से लेकर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सेमी कंडक्टर की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार, 40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम, और कई सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव जैसी बातें निर्मला सीतारमण के भाषण में छाई रहीं। लेकिन ग्रामीण भारत के मजदूर-किसान, बेरोजगार युवा, छोटे और मध्यम कारोबारी, गृहणियां जिन रोजमर्रा के संकटों से दो-चार होती हैं, उस पर बजट लगभग खामोश रहा। सरकार मनरेगा की जगह वीबी जीरामजी कानून लाकर उसके प्रचार के लिए विज्ञापन पर भारी खर्च कर रही है। लेकिन बजट भाषण में इस बारे में चुप्पी बता रही है कि ग्रामीण भारत से मोदी सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। खेती-बाड़ी पर विविधकरण और नारियल, कोको, चंदन और मेवे जैसी 'उच्च मूल्य वाली फसलों' पर बजट भाषण में बात हुई। इससे संपन्न व्यावसायिक किसानों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन उन अनाज किसानों के लिए सीधे तौर पर किसी मदद की बात नहीं की गई जो भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती में बढ़ती लागत या फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों का भाषण में कोई जिक्र नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सही कहा है कि यह बजट देश की समस्याओं से आंख मूंदने वाला है। राहुल गांधी ने लिखा कि देश में युवा बेरोजगार हैं, उत्पादन गिर रहा है, निवेशक पूंजी बाहर निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से घट रही है और किसान संकट में हैं। वैश्विक स्तर पर आने वाले झटकों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बजट इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करता है और आंखें मूंदने वाला है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा बजट है जो सुधार से इनकार करता है और भारत के असली संकटों के प्रति अंधा बना हुआ है। हकीकत यही है कि इस बजट में देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ चुकी आर्थिक असमानता पर कोई चिंता नहीं व्यक्त की गई है और न ही एससी, एसटी, ओबीसी, कमजोर आर्थिक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता दी गई है। मोदी सरकार हर साल नए तरह के सपने बजट में दिखाती है और पिछले सपनों को भूल जाती है। जैसे अब मेक इन इंडिया पर कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना घोटाला हुआ, यह हाल ही में आई रिपोर्ट्स से पता चलता है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार के बजट में न महिलाओं के लिए कोई बड़ी पहल है, न इस बात की चिंता कि रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए।

गजल

जब-जब भी अखबार पढ़ा
यार लगा बेकार पढ़ा
पढ़कर मैं भोंचक्का हूं
रिश्तों में बाजार पढ़ा
कितनी झूठी खबरें हैं
पतझड़ एक बहार पढ़ा
हद है घुप्प अंधेरा भी
लोगों ने उजियार पढ़ा
क्यों घातक हथियारों को
हम सब ने औजार पढ़ा

-मिन्टू कुमार

जयंती

राम सिंह

जन्म-3 फरवरी, 1816, पंजाब, मृत्यु-1885, म्यांमार, 'नामधारी संप्रदाय' के संस्थापक थे। सतगुरु राम सिंह तत्कालीन समय के महान समाज सुधारक, धर्मगुरु और स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध तो संघर्ष किया ही, साथ ही वे विदेशी शासकों के विरुद्ध भी एक कारगर संग्राम के सूत्रधार बने थे। उनकी विचारधारा से अंग्रेज इतना परेशान हुए कि उन्हें बंदी बनाकर रंगून (अब यांगून), बर्मा (वर्तमान म्यांमार) भेज दिया गया।

पुण्यतिथि

अल्ला रक्खा खाँ

जन्म-29 अप्रैल, 1919, मृत्यु-3 फरवरी, 2000, सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। इनका पूरा नाम पूरा नाम कुरैशी अल्ला रक्खा खाँ है। अल्ला रक्खा खाँ अपने को पंजाब घराने का मानते थे। अल्ला रक्खा खाँ के पुत्र का नाम जाकिर हुसैन है जो स्वयं प्रसिद्ध तबला वादक हैं।

कल मिलेंगे

नौकरानी-मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए
मालकिन-अगर तू छुट्टी पर चली गई,
तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा?
टिफिन कौन पैक करेगा, कपड़े कौन धोएगा,
उनको टाइम से दवाई कौन देगा?
नौकरानी (शरमाते हुए)-अगर आप कहें,
तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। **मुद्रक**-देवानंद राय।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

नारी देह, नारी अधिकारः माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

न्यायालय ने शिक्षा को एक मल्टीप्लायर राइट बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया

-ललित गर्ग

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है।

न्यायालय ने शिक्षा को एक मल्टीप्लायर राइट बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निमार्ता, इस विषय को केवल महिलाओं का मामला मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है। आज भारत नए प्रवेश के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरूआत है, मंजिल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार हैं।
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भारत ने बिछाई बड़ी कूटनीतिक बिसात तो सौदेबाजी की मेज पर भागता हुआ आया अमेरिका

अमेरिका को भी समझना होगा कि शुल्क की लाठी से साझेदारी नहीं चलती। यदि वह भारत को सचमुच चीन का विकल्प बनाना चाहता है तो भरोसा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार पहुंच देनी होगी। भारत के लिए भी संदेश साफ है कि आत्मनिर्भर खनिज और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए बिना कोई सामरिक स्वायत्तता संभव नहीं। बहरहाल, जयशंकर की कूटनीति की खासियत यही है कि वे मुस्कान के साथ कठोर संदेश देते हैं

-नीरज कुमार दुबे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक खींचतान एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। जयशंकर की यह यात्रा आपूर्ति शृंखला, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते पर नए संतुलन की तलाश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहल पर आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले दशक की शक्ति राजनीति खनिज, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमेगी।

इस यात्रा का पहला स्पष्ट लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब यह समझ चुकी हैं कि दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामरिक प्रश्न है। चीन जैसे प्रमुख आपूर्तिकताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की मुहिम में भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत की खनिज क्षमता, विशाल बाजार और तकनीकी मांग उसे इस खेल का केन्द्रीय खिलाड़ी बनाती है।

जयशंकर की यह यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क ने संबंधों में कड़वाहट घोली। अब संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन नरमी दिखा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस से तेल खरीद घटने पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का रास्ता है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करने की अनुमति का संदेश भी दिया गया है। यह सब केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर सौदेबाजी के पत्ते हैं।

दिलचस्प यह है कि इसी बीच भारत ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता पूरा कर लिया। इसने अमेरिका को यह संदेश दिया कि नई दिल्ली विकल्प तलाशने में सक्षम है। अटलांटिक परिषद से जुड़े विशेषज्ञ मार्क लिंस्काट का आकलन है कि भारत यूरोप समझौता अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को तेज कर सकता है। साफ है कि वाशिंगटन भारत को खोना नहीं चाहता। वैसे भी भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बातचीत और सार्वजनिक बयानों से यह आभास भी मजबूत हो रहा है कि दोनों देश लंबित व्यापार समझौते को अब अधिक देर तक टालना नहीं चाहते। पिछले महीनों में फोन पर हुई वाताओं, मंत्रिस्तरीय संपर्क और समान हितों पर दिए गए जोर से यह संकेत मिलते हैं कि माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर की अमेरिका यात्रा को केवल खनिज या सामरिक चर्चा तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे संभावित व्यापार समझौते की राह साफ करने वाली पहल के रूप में भी समझा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह धारणा बन रही है कि यदि इस यात्रा में मुख्य अड़चनों पर सहमति का रास्ता निकलता है तो यह आगे की औपचारिक वार्ता के लिए हरी झंडी जैसा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अंतिम राजनीतिक स्वीकृति देकर समझौते पर मुहर लगा सकती है। यानी यह दौरा भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले की भूमिका भी लिख सकता है।

हम आपको यह भी बता दें कि अपनी यात्रा से पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिकी संसद के सदस्य जिमी पैट्रोनिस, माइक रोजर्स और एडम स्मिथ भी मौजूद रहे। बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल रहे। यह केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि जमीन तैयार करने वाली बातचीत थी। गोर ने भारत को अमेरिका का अहम भागीदार बताया और साझा सामरिक हितों पर जोर दिया। साथ ही अमेरिकी संसदीय दल की जनवरी में नई दिल्ली यात्रा भी रक्षा तकनीक सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास पर केंद्रित रही। संदेश साफ है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों की रीढ़ बन सकता है।

अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के केंद्रीय बजट की घोषणाओं से जोड़कर देखिये। मोदी सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने की योजना सीधे उसी दिशा में जाती है जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभियान के लिए ये खनिज अनिवार्य हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम आयन कोश निर्माण, सौर कांच के लिए सोडियम एंटिमोनेट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान पर मूल शुल्क छूट, मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क गणना से जैव गैस को बाहर रखना और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता को पांच गुना बढ़ाना दिखाता है कि भारत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की नई दौड़ के लिए तैयारी कर रहा है। 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भारत की नई सामरिक दिशा है। निजी भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा कानून भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सच यह है कि दुनिया नए शीत युद्ध जैसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां गोलियों से ज्यादा खनिज, चिप और ऊर्जा की आपूर्ति शृंखला ताकत तय करेगी। जयशंकर की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा समझना भूल होगी। यह भारत की बहुस्तरीय चाल है। एक ओर अमेरिका से तनाव घटाना, दूसरी ओर अपने हितों पर अडिग रहना, और साथ साथ यूरोप, रूस तथा अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। पर भारत अब रक्षात्मक नहीं, सौदेबाज की मुद्रा में दिख रहा है।

अमेरिका को भी समझना होगा कि शुल्क की लाठी से साझेदारी नहीं चलती। यदि वह भारत को सचमुच चीन का विकल्प बनाना चाहता है तो भरोसा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार पहुंच देनी होगी। भारत के लिए भी संदेश साफ है कि आत्मनिर्भर खनिज और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए बिना कोई सामरिक स्वायत्तता संभव नहीं। बहरहाल, जयशंकर की कूटनीति की खासियत यही है कि वे मुस्कान के साथ कठोर संदेश देते हैं। अब देखना यह है कि वाशिंगटन इस संकेत को कितना समझता है। अभी जो तस्वीर उभर रही है वह बताती है कि नई दिल्ली ने खेल समझ लिया है और चाल चल दी है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार

अमेरिका के हमले का जरा भी खौफ नहीं, खुमैनी के मकबरे से दहाड़े खामनेई

(एजेन्सी)।

ईरान के सुप्रीम लीडर आया सैयद अली खामिनी कहीं छुपे नहीं है बल्कि वह कुछ दिनों के बाद खुलकर सामने आए हैं और ना सिर्फ सामने आए बल्कि उनकी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों का करारा जवाब दिया है जिसमें उनके छिपे होने या फिर बंकर में जाने की खबरें फैलाई जा रही थी। दरअसल खामनेई ने कोम में जमकरान मस्जिद का दौरा किया। यह स्थल शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उनकी उपस्थिति ने उनके समर्थकों में विश्वास जगाया है। उन्होंने तेहरान में इमाम खुमेनी के स्मारक का दौरा किया। यह दौरा दहा-ए फज्र यानी इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ की शुरूआत के अवसर पर किया गया। उनकी तस्वीरों के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वे देश की कमान पूरी मजबूती के साथ अभी भी संभाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गरजते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय आयातुल्लाह अली खामिनी की ये टिप्पणियां अब तक की उनके सबसे प्रत्यक्ष धमकी है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कामी के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हमें उकसाया नहीं जाना चाहिए और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या फिर उसे परेशान करेगा।

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान यूरोपीय संघ द्वारा ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के फैसले के बाद आया है। यूरोपीय संघ ने यह कदम ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से की गई खूनी कार्रवाई के मद्देनजर उठाया था। कालिबाफ की इस घोषणा को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है। 2019 में पारित एक कानून के तहत ईरान ने अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को भी इसी कैटिगरी में रखा था।

मारुति सुजुकी ग्राहकों को देगी झटका!

(एजेन्सी)।

भारतीय ऑटो बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा मारुति सुजुकी को मिला। हालांकि, बढ़ती मांग के बीच अब कंपनी को कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की चिंता सताने लगी है।

बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कारों की कीमतों की समीक्षा की जा सकती है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सेल्स एंड मार्केटिंग) पार्थो बनर्जी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कमोडिटी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर भी करीबी नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि उन्होंने साफ किया कि कंपनी एक मार्केट लीडर के तौर पर हमेशा कीमतों में बढ़ोतरी को न्यूनतम रखने की कोशिश करती है, लेकिन एक स्तर के बाद अगर लागत को समायोजित करना मुश्किल हो जाता है, तो उसका असर ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है। हालांकि, फिलहाल कीमत बढ़ाने की समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, पिछले साल के फेस्टिव सीजन के बाद से देश में कारों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सरकार द्वारा छोटे कारों और एसयूवी पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजार में मांग और मजबूत हुई है। इसी का फायदा उठाते हुए मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2025 में अपनी एंट्री-लेवल कारों की कीमतों में कटौती भी की थी।

मांग का स्तर ऐसा रहा कि वह सप्लाई से आगे निकल गई। हालात को देखते हुए कंपनी को जनवरी में बुकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करनी पड़ी, ताकि पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

फिलहाल मारुति सुजुकी पर करीब 1.75 लाख गाड़ियों की पेंडिंग बुकिंग है। उत्पादन सीमाओं के चलते वैगनआर जैसी लोकप्रिय कारों की वेटिंग पीरियड एक महीने से ज्यादा हो चुकी है। कंपनी की फैक्ट्रियां रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में भी काम कर रही हैं ताकि डिलीवरी समय कम किया जा सके।

अचानक अमेरिका निकले जयशंकर, भारत में हलचल, कुछ बड़ा होगा!

(एजेन्सी)।

जिस तरह से भारत ने अमेरिका के टेरिफ की काट के लिए नए-नए फामूर्ले अपनाए हैं, उसे लेकर ट्रंप भी परेशान है। क्योंकि भारत पिछले कई महीनों से अमेरिकी व्यापार का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारत ने कई ऐसे देशों के साथ डील की है जो काफी फायदेमंद हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने वाले हैं। जिन देशों के साथ डील हुई है। उनमें से कई अमेरिका के कट्टर दुश्मन भी हैं। क्योंकि जिस वक्त अमेरिका और यूरोप के रिश्ते तनाव की ओर बढ़े हैं, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो सबसे ज्यादा भारत को ही फायदा पहुंचाने वाला है।

यह डील देखकर ट्रंप घबराए हुए हैं और वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुट गए हैं। इसके लिए हाल ही में ट्रंप की टीमें कई बार दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं। अमेरिका की ओर से लगातार ऐसे कई संकेत मिले हैं कि भारत पर लगाया गया टेररिफ जल्द ही कम हो सकता है। इसी बीच एक ऐसा बड़ा सिग्नल मिला है जिससे लग रहा है कि भारत अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है और इसका संकेत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे से मिला है। खबर है कि जयशंकर एक बड़ी और अहम बैठक के लिए अमेरिका जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और गति देने वाला है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स पर मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई है। जिसमें शामिल होने के लिए 2 फरवरी से 4 फरवरी तक एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर होंगे। वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्कोविय की ओर से बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में एस जयशंकर अमेरिकी सरकार के सीनियर सदस्यों के साथ भी मीटिंग करेंगे। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज पदार्थ हैं जो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से आधुनिक तकनीकों का उत्पादन रुक सकता है क्योंकि इनके विकल्प खोजना बहुत कठिन या महंगा होता है।

कार्लोस अल्कारेज ने रचा नया इतिहास

(एजेन्सी)। मेलबर्न की गर्म शाम में टेनिस इतिहास ने नया मोड़ ले लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में कार्लोस अल्कारेज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को मात देकर वह उपलब्धि हासिल कर ली, जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। स्पेन के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करते हुए खुद को सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी के रूप में दर्ज करा लिया। बता दें कि रॉड लेवर एरीना में खेले गए इस मुकाबले की शुरूआत अल्कारेज के लिए आसान नहीं रही। पहला सेट 2-6 से गंवाने के बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 6-2, 6-3, 7-5 से मुकाबला अपने नाम किया हैं। यह मैच तीन घंटे से अधिक चला और अंत तक रोमांच बना रहा। गौरतलब है कि इस जीत के साथ अल्कारेज ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच को 25वां खिताब जीतने से रोक दिया हैं। जोकोविच इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के सभी 10 फाइनल जीत चुके थे, लेकिन इस बार मेलबर्न में उन्हें पहली बार खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मौजूद जानकारी के अनुसार, अल्कारेज अब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पास भी जीतने का बराबर मौका-रिकी पोंटिंग

(एजेन्सी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि उनके पास अपना दूसरा खिताब जीतने का "किसी भी टीम के बराबर" मौका है और उन्होंने टीम में मौजूद कई ऑलराउंडरों की वजह से टीम की लचीलेपन पर जोर दिया। पोंटिंग, जो सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों में से एक हैं और जिन्होंने टीम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2003 और 2007 तथा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और 2009 में जीत दिलाई, आईसीसी रिव्यू के नवीनतम एपिसोड में बोल रहे थे। 2021 संस्करण के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टी20 विश्व कप में रिकॉर्ड बहुत ही उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले संस्करणों में, भारत और अफगानिस्तान से हारकर वे सुपर आठ चरण में ही बाहर हो गए थे। छह बार के और वर्तमान 50 ओवर के चैंपियन टी20 विश्व कप में 2000 के दशक में टेस्ट और वनडे में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने में सक्षम नहीं रहे हैं। दो साल बाद, पोंटिंग को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जीतने का मौका है, जबकि परिस्थितियाँ और प्रतिभा को देखते हुए मौजूदा चैंपियन भारत स्पष्ट रूप से प्रबल दावेदार है। आईसीसी द्वारा उद्धृत ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में पोंटिंग ने कहा कि अगर आप टीम को देखें, तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी टीम के बराबर मौका है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ, प्रतिभा और खिलाड़ियों के समूह को देखते हुए भारत इस टूर्नामेंट में स्पष्ट रूप से प्रबल दावेदार है।" उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेमीफाइनल तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहेगा। पोंटिंग ने यह भी बताया कि डेविड वार्नर (सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से) और मिशेल स्टार्क (टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से) के संन्यास के बाद टीम में थोड़ा बदलाव होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वधान में दिए गए प्रतीक चिन्ह

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूँ। जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी के नवीन शोरूम पर वर्ल्ड पीस हार्मनी संस्था चेयरमैन हाजी शकील सैफी, नगर विधायक महेश चंद्र गुप्ता भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता का भव्य स्वागत कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। उपस्थिति अतिथियों ने व्यापारियों को भाजपा की नीतियों से अवगत कराया स्वागत समारोह में प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी ने किया समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार बंसल ने की संचालन जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने किया।

वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन हाजी शकील ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को भाजपा के 11 साल के शासन जो सम्मान मिला है वो पिछले सरकारों के शासन काल में नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुस्लिम समाज के लिए कई कल्याण कारी योजनाओं को अमल में लाया गया है। विपक्षी राजनीतिक संगठनों ने मुस्लिम समाज को अपना बंधुआ वोट बैंक समझ लिया किंतु अब मुस्लिम समाज जाग्रत हो गया है। वह भाजपा के नीतियों के साथ खड़ा है इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरंक्षण में वर्ल्ड पीस हार्मनी संस्था के द्वारा पूरे देश में भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

नगर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रही आगामी चुनावों में भाजपा प्रचंड जीत के साथ 2047में विकसित भारत विकासशील भारत का सपना पूर्ण करेगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश एवं देश में व्यापारी समाज के लिए कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि व्यापारी समाज हमेशा से भाजपा के नीतियों से प्रभावित रहा है समय समय पर व्यापारी के मांगो को समयवृद्ध रहकर उनका निस्तारण भी कराया जाता रहा है।

इस अवसर पर प्रदेश मंत्री पवन जैन, अबधेश वर्मा, अवधेश लड्डा, प्रदेश संगठन मंत्री सर्वेश गुप्ता, जिला महामंत्री संजीव आहूजा, जिला कोषाध्यक्ष अमित वैश्य, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर महामंत्री संजय रस्तोगी, जिला उपाध्यक्ष सर्वत्र हमीद खान, जावेद खान, फखरे आलम, सगीर खान, सालिम सैफी, असीम, सुलेमान, कैफ, फतेह मोहम्मद, सुहेल सैफी सुजीत गुप्ता, मजरूल सैफी, प्रमोद गुप्ता शाहिद सैफी, अजीम सैफी, कय्यूम सैफी, आसिफ सैफी, नुमान सैफी आदि लोग मौजूद रहे।

2026-27 के बजट से शक्तिपुंज बनेगा भारत: सुभाष चन्द्र

संजना भारती संवाददाता

करनाल। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चन्द्र ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है।

केंद्रीय वित्तमंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट भारत को एक शक्तिपुंज राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे देश की आर्थिक मजबूती को नई गति मिलेगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा सुभाष चन्द्र ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और व्यापारी सहित समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करता है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों की विश्वसनीयता और अधिक बढ़ेगी तथा समावेशी विकास की नींव और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि बजट में छोटे एवं धार्मिक शहरों के विकास के साथ-साथ 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास भी सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि बजट में खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

वहीं बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर किए गए प्रावधान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे।सुभाष चन्द्र ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

नगर निगम करेगा 5.49 लाख रुपये की वसूली: डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। नगर निगम करनाल द्वारा निगम की दुकानों का किराया लंबे समय से जमा न करवाने वाले किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने ऐसे 15 किराएदारों की पहचान कर ली है, जिनकी दुकानों को जल्द ही सील कर निगम के कब्जे में लिया जाएगा। इन दुकानों पर कुल 5 लाख 49 हजार 129 रुपये का बकाया किराया जमा है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि इन सभी किराएदारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे तथा अंतिम नोटिस देकर बकाया राशि समय रहते जमा करवाने का अवसर भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद किराएदारों ने नगर निगम के निर्देशों की पालना नहीं की। ऐसे में अब हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जिन दुकानों को सील किया जाना है, उनमें 12 दुकानें गांव उचानी, एक दुकान कर्ण पार्क मार्केट तथा दो दुकानें गांव कम्बोपुरा में स्थित हैं। दुकानों के सील होने के बाद नगर निगम द्वारा नियमानुसार बकाया किराए की वसूली संबंधित किराएदारों से की जाएगी। डॉ. वैशाली शर्मा ने नगर निगम द्वारा की जा रही रिकवरी का ब्यौरा देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 85 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। वहीं, जनवरी माह में 13 लाख 51 हजार 364 रुपये की रिकवरी की गई है, जिसमें मूल बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आय बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।

नगर निगम आयुक्त ने सभी किराएदारों से अपील की है कि वे समय पर किराया जमा करवाकर निगम का सहयोग करें। उन्होंने डिफॉल्टर किराएदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बकाया राशि शीघ्र जमा नहीं करवाई गई, तो संबंधित दुकानों को सील कर नगर निगम अपने कब्जे में ले लेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

केंद्रीय बजट से हरियाणा को कुछ नहीं मिला, जनता निराश: पराग गाबा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा ने केंद्रीय बजट प्रतिक्रिया व्यक्त कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पूरी तरह निराशाजनक है और इसमें हरियाणा प्रदेश के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। पराग गाबा ने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बजट से राहत की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बजट में हरियाणा के लिए कोई ठोस योजना या विशेष प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, बेरोजगार युवाओं, दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और व्यापारियों सभी वर्गों को इस बजट ने निराश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान पहले से ही फसलों के उचित दाम, बढ़ती लागत और कर्ज की मार झेल रहे हैं, लेकिन बजट में उनके लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई। इसी तरह प्रदेश का युवा वर्ग रोजगार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। पराग गाबा ने कहा कि दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी बजट में केवल दिखावटी घोषणाएं की गई हैं, जबकि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए भी बजट में कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है।

नपा ने चलाया अतिक्रमण अभियान, 4 फरवरी तक दुकानों के आगे से शेड और समान उठाने की दी चेतावनी

संजना भारती संवाददाता

असंध। नगर कर करनाल रोड बस स्टैंड और जींद चौक पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर नपा प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नपा कर्मचारियों ने दुकानदारों के आगे रखा समान हटवाया व नालो से आगे बड़े शैडो को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी की चार फरवरी तक ऐसे हटवा ले अन्यथा जुमार्ने के साथ कारवाही अमल में ले जायगी। इस मोके पर एक दुकानदार कबाड़ में आग लगाते हुए मोके पर पकड़ा गया जिसका पांच सौ रु का चालान काट दिया और सभी दुकानदारों को चेतावनी दी की कबाड़ को सुबह कबाड़ वाली गाड़ी में डालें न की आग लगाए।

नगर पालिका सचिव प्रदीप ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर मुनादी करवाई गई थी जिसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सचिव ने कहा की आज दुकानदारों को चेतावनी अभियान चलाया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नपा प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर सहयोग करें ताकि जाम समस्या से छुटकारा मिले व शहर की सुंदरता भी बढ़े। अतिक्रमण अभियान में बिल्डिंग इंस्पेकर दलबीर जागलान, नरेंद्र, नपा प्रेरक जसमेर, अजमेर व दीपक व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

10 फरवरी से जिले के 63 लाख लोगों को खिलाई जाएगी सर्वजन दवा: सीएस

संजना भारती संवाददाता

मोतिहारी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) के सहयोग से मीडिया कार्यशाला का आयोजन जिले के सिविल सर्जन डॉ दिलीप कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

- राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एमडीए के तहत मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन
- फाइलेरिया मरीज को मिला विकलांगता प्रमाण पत्र

मौके पर सिविल सर्जन डॉ दिलीप कुमार ने बताया की जिले भर में 10 फरवरी से एमडीए कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की जिले के 63 लाख योग्य व्यक्तियों को सर्वजन दवा खिलाई जाएगी, इस दवा का सेवन हाथी पाँव, फाईलेरिया से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपील किया की अभियान की सफलता हेतु सभी लोग सर्वजन दवा जिसमे डीईसी एवं अलबेण्डाजोल की गोली है, उसे आशा या स्वास्थ्य कर्मियों के देखरेख में उनके सामने अवश्य खाए।

कार्यक्रम में उन्होंने बताया की जिले में सिफार के सहयोग से सीएचओ लीड रोगी हितधारक मंच का गठन हुआ है, जो फाइलेरिया सहित अन्य बीमारियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सहयोग कर रही है। सीएचओ लीड पीएसपी सदस्य सह वोलेनटियर मधुबन प्रखंड जिताउरा के जयशंकर यादव मौजूद थे, जिन्हे सीएस डॉ दिलीप कुमार, एसीएमओ एस एन सत्यर्थी, के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिया गया। सीएस ने कहा की अभियान के पूर्व जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक किया जा रहा है जिसमे पीआरई सदस्य, जीविका, आंगनबाड़ी, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि आदि जन-जागरूकता फैला रहे है।

11 फरवरी 2026 को 'महा-अभियान इस अभियान के तहत 10 से 24 फरवरी के बीच आशा दीदी घर घर जा कर दावा खिलायेगी, वहीं 11 फरवरी को 'महा-अभियान के लिए बिहार सरकार ने एक करोड़ लोगों को दावा खिलाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिविर लगाकर जीविका दीदी एवं उनके परिवार के लोगों को दवा खिलाया जाएगा। फिर 25 से 27 फरवरी को स्कूल मे बूथ लगा कर स्कूल के बच्चों को दावा खिलाया जाएगा। जिले में कुल 62,99,129 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 3,166 टीमें और 316 पर्यवेक्षक मुस्तैद रहेंगे। सभी पात्र व्यक्तियों को एलबेंडाजोल की एक गोली चबाकर खानी है, जबकि डीईसी की गोलियां निगलना है जिसे उम्र के अनुसार दी जाएंगी।

मौके पर डीभीडीसीओ डॉ शरत चंद्र शर्मा, जिला महामारी पदाधिकारी डॉ राहुल राज, डीपीएम ठाकुर विश्व मोहन, डीसीएम नंदन झा,अस्पताल प्रबंधक कौशल डूबे, डब्लूएचओ एसएमओ मनोज तुमराडा, पिरामल डीएल मुकेश कुमार, भीडीसीओ कंसलटेंट, भीडीसीओ, सिफार प्रतिनिधि उपस्थित थें।

उर्मिला कासनियां महाराजा सूरजमल संगठन महिला विंग की जिलाध्यक्ष नियुक्त

संजना भारती संवाददाता

श्रीगंगानगर। महाराजा सूरजमल संगठन महिला विंग जिलाध्यक्ष पद पर सक्रिय कार्यकर्ता उर्मिला कासनियां को नियुक्त किया गया है। राजस्थान महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष बबीता कासनिया ने संगठन के अध्यक्ष मनोज कुमार इंदौलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस चौधरी एवं महिला विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता फौजदार से विचार-विमर्श के पश्चात सुखाडिया नगर निवासी उर्मिला कासनियां को महिला विंग श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है कि उर्मिला कासनियां की निर्देशन क्षमता, संघर्ष, संगठनात्मक दक्षता, समर्पण तथा निरंतर सक्रियता से श्रीगंगानगर में संगठन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों को नई गति मिलने के साथ-साथ जिला स्तर पर एक सशक्त, अनुशासित एवं सामाजिक तौर पर संगठन मजबूती से स्थापित होगा। राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि उर्मिला कासनियां के नेतृत्व में, महाराजा सूरजमल संगठन समाजहित, संगठन विस्तार तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा एवं महिला सशक्तिकरण व संगठन विस्तार के कार्यों में आपकी भूमिका प्रेरणादायी रहेगी। नवनियुक्त महिला विंग जिलाध्यक्ष उर्मिला कासनियां ने बताया कि महाराजा सूरजमल संगठन का मुख्य उद्देश्य भरतपुर के वीर जाट शासक महाराजा सूरजमल की न्यायप्रियता, दूरदर्शी सोच तथा आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का विश्वास दिलाया है। वर्तमान में उर्मिला कासनियां विश्व हिन्दू परिषद की जिला सह संयोजिका का दायित्व भी बखूबी निभा रही है।

गुरु रविदास जी ने समाज को दी नई दिशा: शेरी

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। गुरु रविदास जी ने जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को नई दिशा दी। उन्होंने अपने दोहों और वाणी के माध्यम से भक्ति, समानता और मानवता का संदेश दिया। उपरोक्त विचार हरियाणा किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शेर प्रताप शेरी ने गांव जयसिंहपुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर बोलते हुए कहे। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। शेर प्रताप शेरी का ग्रामीणों ने फुल मालाए पहनाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी को एक महान आध्यात्मिक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु रविदास ने हमेशा ऊंच नीच, छुआ छूत, जातीय भेदभाव जैसी अनेक कुरीतियों के खिलाफ अपने दोहों से समाज को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। गुरु रविदास ने आपसी भाईचारे, समरसता और समानता का संदेश दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुनील सिंधड, सिराजुद्दीन दूपेडी, पूर्व सरपंच कपिल, जोगिंद्र, राजकुमार, सतीश, सत्यवान, गुलाब, सुकरमपाल सिंधड सहित अन्य मौजूद रहे।

ऐतिहासिक रहा बिहार प्रदेश अग्रहरि वैश्य समाज के भव्य शपथ-ग्रहण समारोह

संजना भारती संवाददाता

पटना। राजधानी पटना के गौरीचक में बिहार प्रदेश अग्रहरी वैश्य समाज एवं जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और समाज हित में ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ली।

बिहार राज्य अग्रहरि समाज के तत्वावधान एवं पटना नगर अग्रहरि वैश्य समाज के सहयोग से आयोजित जनगणना, शपथ ग्रहण एवं कार्यकारिणी के गठन का समारोह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।कार्यक्रम की शुरूआत महाराजा अग्रसेन जी की तैलिय चित्र पर पुष्पांजलि एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और स्वागत गान से हुई। मंच पर मंचासिन प्राधिकारियों में विशेष रूप से केंद्रीय अग्रहरि समाज के महामंत्री अशोक अग्रहरि एवं बिहार प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू गरिमामयी उपस्थिति रही। शपथ ग्रहण समारोह होने के तत्पश्चात जनगणना पर विशेष चर्चा हुई।कार्यक्रम के बीच में स्वागत गान एवं उद्घोषिका द्वारा संगीत का भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पप्पू कुमार अग्रहरी, गौरीचक द्वारा कार्यक्रम का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया गया।

समारोह में प्रदेश एवं जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षिविद और बड़ी संख्या में अग्रहरि समाज के लोग उपस्थित रहे। मौके पर पहुंचे सभी गण्यमान्य पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया। तत्पश्चात विधिवत शपथ दिलाई गई।

भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण और अग्रहरि समाज की जनगणना कराने पर विशेष जोर दिया ताकि अपनी जनसंख्या सरकार से विधानसभा एवं विधान परिषद में उचित हिस्सेदारी की मांग कर सके। वक्ताओं ने कहा कि समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ताकि आने वाली पीढ़यों को बेहतर दिशा मिल सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी करा कि नवगठित जिला स्तरीय टीम समाज के हित में सकारात्मक भूमिका निभाएगी और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

शपथ ग्रहण समारोह के सफल आयोजन से समाज में उत्साह और नई का संचार देखने को मिला। कार्यक्रम में काफी सख्या में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रहरी वैश्य समाज की एकता और संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह जानकारी बिहार प्रदेश अग्रहरी वैश्य समाज के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता ने दी है।

परीक्षा केंन्द्र पर आवश्यक व्यवस्था को लेकर सीवान शहर के वीएम हाई स्कूल के केंन्द्राधीक्षक से जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने माँगा स्पष्टीकरण

एसबी संवाददाता

सिवान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित वर्ष 2026 की इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2026 दिनांक 02.02.2026 से 13.02.2026 तक निर्धारित है।उक्त के आलोक में दिनांक 31.01.2026 को जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस अधीक्षक,सिवान के द्वारा उक्त परीक्षा की आवश्यक तैयारी करने हेतु संयुक्त रूप से ब्रिफिंग किया गया था। ब्रीफिंग में परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया था।

सोमवार को जिला पदाधिकारी सिवान विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा उक्त दोनों परीक्षा केन्द्र का भ्रमण के दौरान पाया गया कि परीक्षा केंन्द्र पर बेंच डेस्क, समुचित लाईट, पेयजल एवं अन्य आवश्यक तैयारी स-समय नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि केंद्राधीक्षक के द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2026 को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है, और इस कार्य में पर्याप्त रूचि भी नहीं ली जा रही है। यह आचरण कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अकर्मण्यता को दर्शाता है। जिला पदाधिकारी सिवान ने अपने स्पष्टीकरण पत्र में कहा है कि पत्र प्राप्ति के 02 दिनों के अंदर उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपकी इस लापरवाही एवं अकर्मण्यता के लिए आपके विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई किया जाय? यदि निर्धारित समय के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/ कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: 9871221635

केंद्रीय बजट 2026 देशवासियों की समृद्धि का संकल्प: जगमोहन आनंद

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे देशवासियों की समृद्धि का संकल्प बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किए गए प्रावधानों से समाज का हर वर्ग सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। किसान, व्यापारी, महिलाएं और विशेष रूप से युवा वर्ग इस बजट की घोषणाओं से उत्साहित हैं।

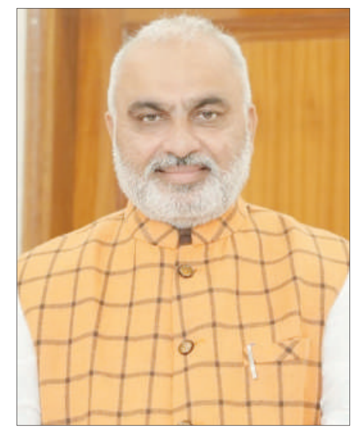

विधायक ने कहा कि बजट में युवाओं की शिक्षा के लिए 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। डिजिटल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों पर फोकस किए जाने से युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप और शिक्षा के क्षेत्र में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, शैक्षणिक ढांचे में बड़े और दूरगामी बदलाव की दिशा में अहम कदम है।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा तोहफा है। इससे महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से जुड़ी घोषणाएं भी जनहित में हैं, जिससे आवागमन और व्यापार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान छोटे और मध्यम उद्योगों को नई गति देगा। इससे स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही किसानों और एग्री इंडस्ट्री की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रावधानों से हरियाणा सहित देशभर के किसानों को लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता इस बजट में स्पष्ट दिखाई देती है।

विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रदेश और देश दोनों के लिए हितकारी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक बजट के रूप में देखा जाएगा।

विजिलेंस ब्यूरो ने क्लर्क को 2700 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई मुहिम के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बठिंडा में तैनात क्लर्क डेविड को 2700 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपी को कन्हैया नगर, जिला बठिंडा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता एजेंट राजा मित्तल के दफ्तर में एक दिहाड़ीदार के रूप में काम करता है और आरटीओ बठिंडा से संबंधित कार्य संभालता है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी आरटीओ बठिंडा में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की ऑनलाइन सत्यापन की ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता की फाइलों का सत्यापन नहीं कर रहा था और उन फाइलों का सत्यापन करवाने के लिए प्रति फाइल 300 रुपये की मांग कर रहा था। आरोपी ने शिकायतकर्ता को बठिंडा के बस स्टैंड पर बुलाया और 2100 रुपये रिश्वत के रूप में लिए तथा फिर गैर-कानूनी रिश्वत के रूप में 3000 रुपये की मांग की।

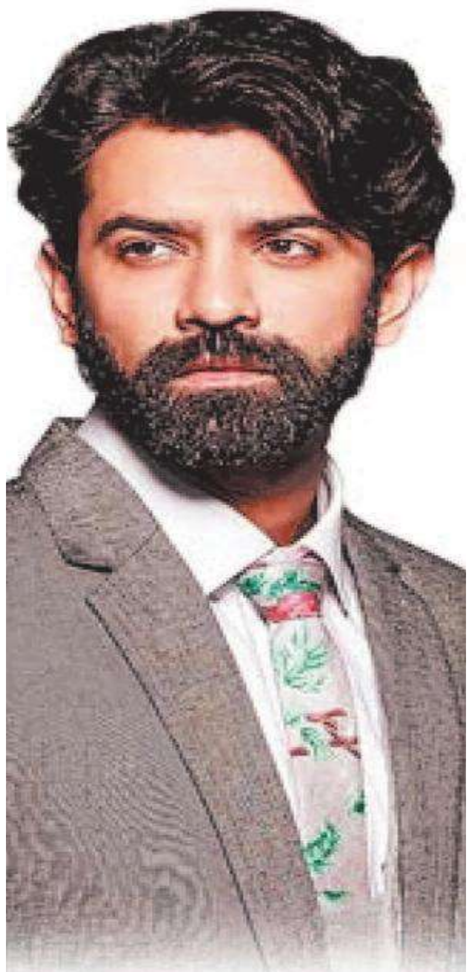

कोहरा 2 में अपने किरदार को लेकर बोले बरुन सोबती

दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली वेब सीरीज कोहरा का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। पहली सीरीज की कहानी, रहस्य और रहस्यमयी वातावरण दर्शकों को इतना पसंद आया कि इसके दूसरे सीजन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।

इस बार की कहानी में रहस्य और मामले पहले से भी ज्यादा जटिल होंगे। इस बार भी अभिनेता बरुन सोबती अपने पहले वाले किरदार अमरपाल गारुडी के रूप में नजर आएंगे। सीरीज में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बरुन ने कहा, इस सीजन में गारुडी पहले से ज्यादा सतर्क है। वह हर कदम पर सोच-विचार करता है और अपने फैसलों और विकल्पों का लगातार मूल्यांकन करता है। गारुडी इस बार नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता है, लेकिन कोहरा की दुनिया में बीते समय और पुराने अनुभव उसे पीछे नहीं छोड़ते। रहस्य इस बार और गहरा है और केस की जटिलता उसकी मानसिक स्थिति और फैसलों में भी दिखती है। बरुन ने कहा, इस सीजन ने मुझे अभिनेता के रूप में नई चुनौतियां दी हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस कहानी में गहराई से जुड़ेंगे। कोहरा 2 की कहानी इस बार जगराना से आगे बढ़ते हुए दलेरपुरा पहुंचती है, जहां माहौल पहले से ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी है। एएसआई अमरपाल गारुडी का तबादला दलेरपुरा पुलिस स्टेशन में हो जाता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है।

इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण मोना सिंह हैं, जो गारुडी की नई कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर की भूमिका निभा रही हैं। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, सोच अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सच तक पहुंचना। जैसे-जैसे वे एक हत्या के मामले की परतें खोलते हैं, वैसे-वैसे उनके अपने अतीत से जुड़े कई दबे हुए राज भी सामने आने लगते हैं। पंजाब की पृष्ठभूमि में बुनी गई यह कहानी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन हर मोड़ पर असर छोड़ती है। यह सीजन 11 फरवरी से नेटफिलक्स पर स्ट्रीम होगी।

रीटा फरेरा के किरदार से खुद को कैसे जोड़ती हैं भूमि?

भूमि पेडनेकर की नई सीरीज 'दलदल' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। इस बार अभिनेत्री एक डीसीपी के रूप में क्राइम से लड़ती नजर आएंगी। इस इंटरव्यू में भूमि ने दलदल की कहानी में दिखाए गए समाजिक मुद्दों समेत इस सीरीज में अपने किरदार और उसके पीछे की गंभीरता के बारे में भी चर्चा की। बातचीत में भूमि ने यह भी बताया कि किस तरह वो अपने किरदार के साथ रिलेट करतीं हैं।

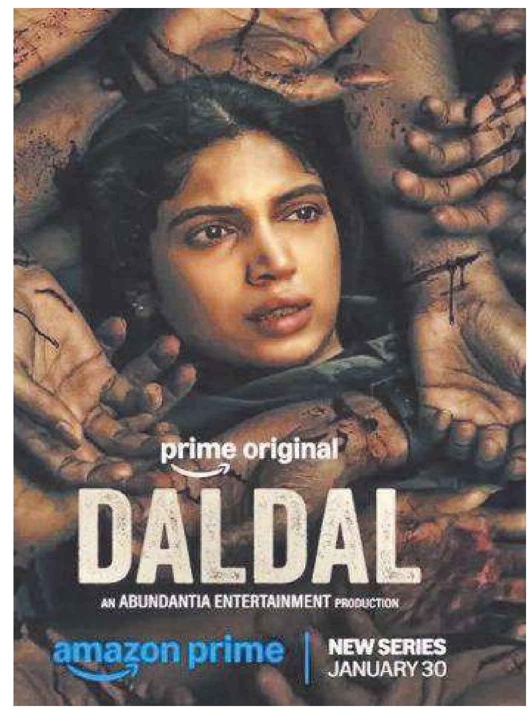

क्यों अलग है 'दलदल' सीरीज?

भूमि पेडनेकर ने इस इंटरव्यू में 'दलदल' के बारे में बात करते हुए कहा, इस शो का अनुभव वैसा ही है जैसे आप किसी चीज में फंसते चले जा रहे हों वही घुटन, वही बेचैनी, वही क्लॉस्ट्रोफोबिक सी फीलिंग। मेरा किरदार उस भावना को बहुत अच्छी तरह समझाता है। हालांकि शो में एक तरह की डार्कनेस है लेकिन इसके साथ ही हल्कापन भी है। यह एक बहुत इंटेलिजेंट और मनोवैज्ञानिक क्राइम ड्रामा है। इस जॉनर में कई शो आए हैं लेकिन फूली फील्स की राइटिंग इसमें एक अलगपन लेकर आती है।

किन मायनों में अलग है रीटा फरेरा का किरदार?

'दलदल' में अपने किरदार डीसीपी रीटा फरेरा के बारे में भूमि ने कई बातें बताईं। भूमि ने कहा, रीटा अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार है, लेकिन वर्दी में और वर्दी के बाहर उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग दिखता है। उसके भीतर गहरी डार्कनेस है, बहुत सा ट्रॉमा है जिससे वह पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। यही इस शो की जड़ है कि हम सब अपने बचपन के घावों को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। इसी कमी ने उसे हर तरह की खुशी से दूर कर दिया। उसके अंदर गुस्सा भी है, हिंसा भी है और उतनी ही गहरी संवेदनशीलता भी। यही उसका दलदल है और यही वह जाल है जिसमें इस शो का हर किरदार अपने अपने तरीके से फंसा हुआ है।

रीटा के व्यक्तिव से समानता महसूस करती हूं

भूमि पेडनेकर ने अमर उजाला को दिए इस इंटरव्यू में अपने और रीटा फरेरा के बारे में बताया, मैं यानी भूमि खुद को रीटा से जिस एक चीज के जरिए जोड़ पाती हूं वह है काम के प्रति उसकी ईमानदारी। रीटा की तरह मेरे अंदर भी अपने काम को लेकर गहरी सच्चाई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि अपने किरदार को जितनी ईमानदारी और सच्चाई से निभा सकूं निभाऊं। शायद यही वह जगह है जहां मैं और रीटा एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी तरह मैं भी अपने काम में पूरी तरह डूब जाती हूं।

फिल्म में दिखेंगी एक नई दीपिका

'जवान' फेम निर्देशक एटली इन दिनों अल्लू अर्जुन के साथ अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चाओं में हैं। हालांकि, अभी तक फिल्म का टाइटल तय नहीं है। बड़े स्तर पर बन रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। अब एटली ने फिल्म को लेकर बात की है। बातचीत के दौरान एटली ने

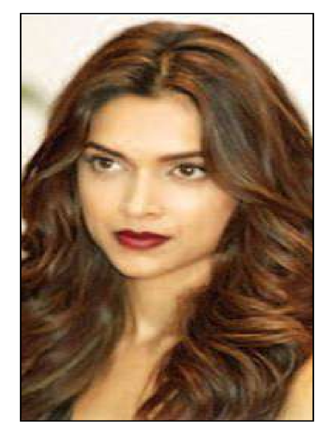

इस फिल्म को लेकर बताया कि टीम फिल्म पर काफी मेहनत कर रही है। इसके बारे में बात करने के लिए उतनी ही उत्साहित है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही है। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया पता चल रहा है। मुझे पता है कि हर कोई फिल्म के बारे में सुनना चाहता है। सच कहूं तो, अपने दर्शकों से भी ज्यादा, मैं उन्हें सब कुछ बताने के लिए उत्सुक हूं। हम इस पर काम करते हुए रातों की नींद हराम कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन हम उतने ही उत्साहित हैं। हम सबके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। एक बार यह बन जाए, तो यकीन मानिए, हर कोई इसका भरपूर आनंद उठाएगा।

'जवान' के बाद फिर से दीपिका पादुकोण के साथ काम करने पर एटली ने कहा कि हां, वो मेरी लकी चार्म हैं। दीपिका के साथ यह मेरी दूसरी फिल्म है और उनके साथ काम करना बेहद शानदार है। वो लाजवाब हैं। मुझे लगता है कि मां बनने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने पर आपको एक बिल्कुल अलग दीपिका देखने को मिलेंगी।

टैलेंट से सफल अभिनेत्री और गायिका बनीं हैं श्रुति हासन

भारतीय सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं, जो सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं हैं। ये नाम अपनी बहुआयामी प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाते हैं। 28 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने वालीं श्रुति कमल हासन ऐसी ही एक शख्सियत हैं। एक सफल अभिनेत्री, गायिका, संगीतकार और परफॉर्मर, जिनकी पहचान केवल एक स्टार किड के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में बनी है।

हासन परिवार में जन्म लेने के बावजूद श्रुति ने अपनी राह खुद बनाई। वह न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक स्थापित गायिका और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। श्रुति ने चेन्नई के एबाकस मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की और दसवीं तक वहीं शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें संगीत और सिनेमा में गहरी रुचि थी। इसी लगाव ने उन्हें आगे चलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग ली।

महज छह साल की उम्र में श्रुति हासन ने अपने पिता की फिल्म थेवर मगन (1992) में पहला गाना गाया, जिसे इलैया राजा ने कंपोज किया था। इसके बाद स्कूल के दिनों में उन्होंने हिंदी फिल्म चाची 420 (1997) में भी गायन किया। साल 2000 में कमल हासन के निर्देशन में बनी फिल्म हे राम में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और उसी फिल्म के लिए हिंदी और तमिल में टाइटल थीम रामा रामा भी गाई। एक अभिनेत्री के तौर पर श्रुति ने वयस्क भूमिका में डेब्यू 2009 में बॉलीवुड फिल्म 'लक' से किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया और यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा।

श्रुति को असली पहचान तेलुगु फिल्म अनागनगा ओ धीरुडु (2011) से मिली। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। रेस गुर्रम (2014) में दमदार भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु मिला। कुल मिलाकर श्रुति के नाम तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स सहित कई सम्मान दर्ज हैं। हिंदी सिनेमा में श्रुति हासन ने डी-डे, रामैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया। जहां कुछ फिल्मों को समीक्षकों की सराहना मिली, वहीं कुछ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अभिनय के साथ-साथ संगीत श्रुति हासन की पहचान का अहम हिस्सा है। वह एक स्थापित पार्श्व गायिका हैं।

शादी और करियर पर विक्रांत सिंह और मोनालिसा ने साझा किए दिलचस्प किस्से

मोनालिसा और विक्रांत रियलिटी शो 50 में एक साथ नजर आ रहे हैं। शो शुरू होने से पहले खास बातचीत में दोनों ने शो के फॉर्मेट, अपने रिश्ते और करियर को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर कीं। बता दें कि मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिसवास है और वे 50 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बिग बॉस 10 के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढी और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई, जहां कई पापुलर शोज में उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाईं।

मोनालिसा को लेकर समाज की सोच पहले निगेटिव थी - विक्रांत

विक्रांत सिंह के मुताबिक, मोनालिसा जब बिग बॉस में आई थी, उससे पहले लोगों की सोच ज्यादातर निगेटिव थी। हम जिस सोसाइटी से आते हैं, वहां खासकर लड़कियों के लिए निगेटिव सोच जल्दी बनती है। घर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में आना गलत मान लिया जाता है। आप सही हों या गलत लोग की नजर में आप गलत ही हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा किरदार चुना जिसे आपको परफॉर्म करना है, तो भी गलत माना जाता है। लोगों ने मोनालिसा के बारे में गलत सोचा। वो लोग बोलने से पहले सोचते नहीं।

शादी के बाद बदली राय, पर सोच धीरे बदलती है

वो आगे कहते हैं, बिग बॉस में आने के बाद कुछ हद तक राय बदली। हमारी शादी हुई तो और भी बदलाव आया। लेकिन सोच बहुत धीरे बदलती है। ज्यादातर लोग निगेटिव जाते हैं। आपकी मेहनत को लोग क्रेडिट नहीं देते कहते हैं अरे इसको ऐसे ही मिल गया होगा। ये सिर्फ मोना के साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ होता है।

50 शो का स्केल देखकर दोनों ने तुरंत हां कहा

रियलिटी शो 50 के बारे में विक्रांत कहते हैं, मेकर्स ने बताया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो बनाना चाहते हैं, 50 सेलेब्स आने वाले हैं। यह सुनकर कोई भी तुरंत सोच लेगा कि भाई मौका मिल रहा है, चौका मार देते हैं। तो हम तो तुरंत तैयार हो गए।

मोनालिसा - 15 नहीं, 50 लोग... फॉर्मेट ही सबसे बड़ा बदलाव

मोनालिसा ने आगे जोड़ा, जब फॉर्मेट सुना तो सबसे पहला सोच यही थी कि बहुत अलग होगा। पहले जब मैं बिग बॉस में गई थी, वहां 15 लोग थे, यहां 50 रहेंगे। और हमें दोनों को साथ बुलाया गया है। बिग बॉस के बाद हमें ज्यादातर रियलिटी शो ही ऑफर होते रहे, जैसे नच बलिये, स्मार्ट जोडी, किचन चैम्पियन यह सब बहुत एक्साइटिंग था। मुझे नए एक्सपीरियंस लेना पसंद है। मैं चाहती हूं कि करियर वाइज हमेशा कुछ नया करूं और लकी हूं कि मिल भी जाता है।

क्या रियलिटी शो रिश्ते पर असर डालते हैं?

विक्रांत साफ कहते हैं, पर्सनल लाइफ और घर में रहना एक बात है। लोगों के बीच जाकर कैसे रियेक्ट करते हो, वो दूसरी बात है। ऊपर से गेम खेलना है। तो मुझे लगता है कि डिफरेंसेज दिखेंगे ही। घर में भी कई मुद्दों पर हम सहमत नहीं होते। कोई प्लानिंग नहीं है हमारी। लोग मोना के नेचर को जानते हैं और मेरे लोग मुझे जानते हैं। मुझे उतना नहीं देखा है लोगों ने, तो इस शो से लोग मुझे पर्सनली जानेंगे। जो भी होगा नैचुरली होगा।

विक्रांत अपने प्रोफेशनल फैसलों पर मोना पर कितना निर्भर हैं?

विक्रांत कहते हैं, एक पैसे का निर्भर नहीं हूं। ये अच्छा नहीं है, लेकिन सच है। मोना को भी मालूम है। मैं भी ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूं, जहां लोग मुझे जानें। जहां भी गया हूं, मेरे लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूं। सुनूंगा तभी जब बात में लॉजिक हो, वरना नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस शो से मुझे मेरी पहचान मिले।

मोनालिसा किस तरह के रोल करना चाहेंगी?

मोनालिसा बताती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर करना चाहती हूं। आजकल वेब सीरीज में इतने रियल रोल देखते हैं कि लगता है, ऐसा मैंने अभी तक किया ही नहीं है। रियल, नेचुरल, लोकेशन पर शूट बहुत कुछ बाकी है। पांच छह साल पहले पूछते तो कहती कि करीना की जब वी मेट जैसा चुलबुला रोल करना चाहती हूं। लेकिन अब उससे हटकर भी कई कैरेक्टर करना है।